



Neutral Citation No. - 2026:AHC:35023-DB

02.02.2026 को सुरक्षित

17.02.2026 को पारित

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक अपील संख्या - 2955 वर्ष 1985

बट्टू सिंह और अन्य

.....अपीलकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

अपीलकर्ता(गण) के अधिवक्ता: प्रखर श्रीवास्तव, ब्रह्म सिंह, पं. मोहन चंद्र, सुशील कुमार तिवारी

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता: ए.जी.ए.

न्यायालय संख्या - 46

माननीय न्यायमूर्ति सिद्धार्थ

माननीय न्यायमूर्ति जय कृष्ण उपाध्याय

(न्यायमूर्ति सिद्धार्थ द्वारा प्रदत्त)

1. श्री प्रारब्ध जैन और श्री अनुराग श्रीवास्तव, जो अपीलकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता श्री प्रखर श्रीवास्तव के ब्रीफ होल्डर हैं; राज्य की ओर से विद्वान ए.जी.ए.-। श्री जी.एन. कनौजिया को सुना गया और निर्णय तथा विचारण न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया।

2. ऊपर बताई गई आपराधिक अपील, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मुरादाबाद द्वारा सत्र विचारण संख्या 25/1985 में दिनांक 31.10.85/2.11.85 को पारित निर्णय और आदेश के विरुद्ध दायर की गई है। इस निर्णय में अपीलकर्ताओं को धारा 302/149 भा.दं.सं. के तहत आजीवन कारावास, धारा 147 भा.दं.सं. के तहत 1 वर्ष का कठोर कारावास, धारा 323/149 भा.दं.सं. के

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



तहत 6 माह का कठोर कारावास और पुनः धारा 323/149 भा.दं.सं. के तहत 6 माह के कठोर कारावास की सज़ा सुनाई गई है; ये सभी सज़ाएँ एक साथ चलेंगी।

3. अभियोजन पक्ष का प्रकरण यह है कि यह घटना कथित तौर पर 23.6.1984 को दोपहर लगभग 1:00 बजे, थाना कुरफतेहगढ़ के गाँव देवरा खास में, अभियुक्त बट्टू और शिकायतकर्ता सावले (पी.डब्ल्यू.1) के घरों के बीच स्थित एक सार्वजनिक रास्ते पर हुई थी। उक्त सावले द्वारा 23.6.84 को ही दोपहर 2:30 बजे थाना कुरफतेहगढ़ में एक लिखित रिपोर्ट (प्रदर्श क-1) दर्ज कराई गई थी। इसमें आरोप लगाया गया था कि सावले अपने भाइयों, रक्षपाल और सोरन के साथ, खेतों की जुताई करने के बाद जंगल से लौट रहा था। रक्षपाल और उसके पीछे सोरन आगे चल रहे थे, और सावले उनके पीछे था। उनका अपना घर, अभियुक्त बट्टू के घर से, बीच में पड़ने वाले रास्ते के दूसरी ओर स्थित था। अभियुक्त बट्टू, अपने साथी अभियुक्तगण सत्यपाल, मेहरबान और बाबू के साथ मिलकर, रास्ते की ज़मीन से मिट्टी खोद रहा था और उसे अपने घर के किनारे जमा कर रहा था। सह-अभियुक्त दीना, बृज लाल, शिवपाली, मुंशी जी, बाबू जी, कुंवर सेन, नन्हे, किशन पाल, किशन लाल और काले वहाँ बैठे हुए थे। ये लोग भाले और लाठियों से लैस थे। जब रक्षपाल और सोरन ने इसका विरोध किया, तो सभी 14 अभियुक्त उन पर टूट पड़े और अपने-अपने भालों और लाठियों से उन्हें पीटना शुरू कर दिया। रक्षपाल और सोरन द्वारा मचाए गए शोर को सुनकर, लाले, नत्थू, राम चरण, शिवम पाल, राम गुलाम और जरकी घटनास्थल पर पहुँचे। अभियुक्तगण ने लाले को भी पीटा। सावले भी घटनास्थल पर पहुँचा, लेकिन जैसे ही ये अभियुक्त उसकी ओर बढ़े, वह भाग गया और एक तरफ खड़ा हो गया। पिटाई करने के बाद, ये अभियुक्त पूरब दिशा में जंगल की ओर भाग गए। रक्षपाल के पास पहुँचने पर, सावले ने पाया कि रक्षपाल की मृत्यु हो चुकी थी। उसने सोरन और लाले के शरीर पर भी चोटें देखीं। सावले ने रक्षपाल के शव को अपने घर के आँगन में पहुँचाया और फिर घायल सोरन और लाले को पुलिस थाने ले जाकर पूर्वोक्त एफआईआर दर्ज करवाई।

4. पुलिस ने एक मामला दर्ज किया और विवेचना शुरू कर दी। उसी दिन, रक्षपाल के शव को हिरासत में ले लिया गया और एक पंचायतनामा (प्रदर्श क-4) तैयार किया गया। शव को विधिवत सील किया गया और फिर कांस्टेबल सत्य वीर त्यागी और जमुना प्रसाद के माध्यम से पोस्टमार्टम जाँच के लिए भेजा गया। यह पोस्टमार्टम जाँच डॉ. एन.के. गुप्ता द्वारा 24.6.84 को दोपहर 3.10 बजे की गई (प्रदर्श क-16)। फोटो नाश (प्रदर्श क-5), 7 चालान नाश (प्रदर्श क-6) और आवश्यक “अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



पत्र (प्रदर्श क-7 और का-8) भी तैयार किए गए और शव के साथ भेजे गए। घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और एक रेखाचित्र (प्रदर्श क-9) तैयार किया गया। लाठी, फावड़ा और चारपाई के खून से सने बान (प्रदर्श क-10 से का-13) के संबंध में फर्द बरामदगी भी तैयार किए गए। घायल सोरन सिंह और लाले के खून से सने कपड़ों के संबंध में एक और फर्द बरामदगी (प्रदर्श क-15) 24.6.84 को तैयार किया गया। घायल लाले और सोरन की मेडिकल जाँच 23.6.84 को ही क्रमशः रात 9.15 बजे और 9.30 बजे पी.एच.सी. कुंदरकी में की गई और चोट रिपोर्ट (प्रदर्श क-18 और का-17) तैयार की गई। अंततः, विवेचना पूरी करने के बाद, पुलिस ने 24.7.84 को इन अभियुक्तगण के खिलाफ एक आरोप-पत्र (प्रदर्श क-14) प्रस्तुत किया।

5. ऊपर बताई गई आरोप-पत्र के आधार पर, मजिस्ट्रेट ने मामले का संज्ञान लिया। तय प्रक्रिया के अनुसार, विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मुरादाबाद ने 7.1.85 के आदेश द्वारा इस वाद को सत्र न्यायालय को सुपुर्द कर दिया।

6. अभियुक्तों और उनके अधिवक्ताओं की बात सुनी गई और 12.3.85 को उनके खिलाफ ऊपर बताए गए आरोप विरिच किए गए। अभियुक्तों ने आरोपों को स्वीकार नहीं किया और खुद को निर्दोष बताया।

7. अपनी बात साबित करने के लिए, अभियोजन पक्ष ने सावले (पी.डब्ल्यू.1), सोरन (पी.डब्ल्यू.2) और नत्थू सिंह (पी.डब्ल्यू.3) को घटना के गवाहों के तौर पर पेश किया। पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज होने की बात साबित करने के लिए कांस्टेबल, ब्रिज फान सिंह (पी.डब्ल्यू.4) से पूछताछ की गई। उपनिरीक्षक एस.के. सागर (पी.डब्ल्यू.5) इस मामले के विवेचना अधिकारी हैं।

8. बचाव पक्ष ने डॉ. ए.के. महेन्द्र (डी.डब्ल्यू.1) और बाबू सिंह (डी.डब्ल्यू.2) को गवाह के तौर पर पेश किया।

9. इस अपील के लंबित रहने के दौरान, अपीलकर्ता संख्या 1 - बट्टू सिंह (बेनी के बेटे), अपीलकर्ता संख्या 7 - मुंशी जी (बृजपाल के बेटे) और अपीलकर्ता संख्या 11 - किशन पाल (नानहे के बेटे) को छोड़कर, बाकी सभी अपीलकर्ताओं की मृत्यु हो गई। पिछले आदेशों के अनुसार, अन्य अपीलकर्ताओं के खिलाफ अपील को समाप्त मानकर खारिज कर दिया गया है। इसलिए, अपील की सुनवाई केवल ऊपर बताए गए जीवित अपीलकर्ताओं संख्या 1, 7 और 11 की ओर से की गई है।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



10. इस घटना के बारे में सावले (पी.डब्ल्यू.1), सोरन (पी.डब्ल्यू.2) और नत्थू (पी.डब्ल्यू.3) ने गवाही दी है। सावले ने गवाही दी कि मृतक रक्षपाल उसका सगा भाई था। सोरन (पी.डब्ल्यू.2) भी उसका सगा भाई है। वे तीनों सुबह-सुबह अपने खेतों में हल चलाने गए थे। वह अपने खेत में अलग से हल चला रहा था, जबकि रक्षपाल और सोरन मिलकर दूसरे खेत में हल चला रहे थे। खेत पर ही सावले की पत्नी उन्हें खाना देने आई और उसने उन्हें बताया कि अभियुक्त, बट्टू और अन्य लोग उनके घरों के बीच के रास्ते से मिट्टी खोद रहे हैं और रास्ते के अपनी तरफ एक चबूतरा बना रहे हैं। सावले ने उससे कहा कि वह कोई हंगामा न करे और वह घर पहुँचकर इस मामले को देखेगा। खेतों से लौटते समय, रक्षपाल और उसके पीछे सोरन आगे चल रहे थे, और वह उनसे लगभग 25 कदम पीछे था। वह और सोरन अपने कंधों पर हल उठाए हुए थे, जबकि रक्षपाल बैलों को ले जा रहा था। घर के पास पहुँचने पर उन्होंने अभियुक्त, बट्टू और अन्य लोगों को ऊपर बताया गया काम करते हुए देखा। रक्षपाल ने बैलों को छोड़ दिया और उस जगह के पास जाकर बट्टू और अन्य लोगों के इस काम का विरोध किया कि वे रास्ते से मिट्टी खोदकर उसे संकरा कर रहे हैं। अभियुक्तगण ने उसे गालियाँ दीं और उस पर हमला किया, और फिर सोरन (पी.डब्ल्यू.2) भी दौड़कर उस जगह पर पहुँचा। उसे भी पीटा गया। उनके द्वारा मचाए गए शोर को सुनकर गाँव के कई अन्य लोग वहाँ जमा हो गए, जिनमें राम चरण, नत्थू, शिशुपाल, लाले और जानकी शामिल थे। लाले उनसे आगे था, और जब उसने रक्षपाल और सोरन की पिटाई का विरोध किया, तो अभियुक्तगण ने उस पर भी हमला किया और उसे घायल कर दिया। सावले ने गवाही दी कि उस समय अभियुक्त बट्टू, मेहरबान, सतपाल और बाबू मिट्टी खोद रहे थे और रास्ते के अपनी तरफ एक चबूतरा बना रहे थे। अन्य सह-अभियुक्त, यानी बृज लाल, शिवपाली, दीन, मुंशी जी, कुंवर सेन, नरहे, किशन, किशन लाल, बाबू जी और काले, बट्टू के घर में बैठे हुए थे। जब बट्टू और तीन अन्य लोगों ने रक्षपाल पर हमला किया, तो दूसरे सह-अभियुक्त भी बाहर आ गए और पिटाई में शामिल हो गए। उस समय बट्टू, मेहरबान, सतपाल और ब्रिज लाल ने भाले का इस्तेमाल किया, जबकि बाकी लोगों ने लाठियों का इस्तेमाल किया। बट्टू ने रक्षपाल पर भाले से वार किया और मेहरबान ने भी रक्षपाल पर भाले से वैसा ही वार किया। हालाँकि, अभियुक्त सतपाल ने अपने भाले का इस्तेमाल उसके हथ्थे की तरफ से लाठी की तरह किया। अभियुक्त किशन पाल ने रक्षपाल पर लाठी से वार किया। उसने आगे बताया कि सोरन (पी.डब्ल्यू.-2) को किशन लाल, बाबू, काले, बाबू जी और नन्हे ने लाठी से पीटा, जबकि लाले को अभियुक्त ब्रिज

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



लाल, सियोपाल, दीना, मुंशी जी और कुंवर सेन ने लाठी से पीटा। उसने कहा कि यह घटना पाखर के पेड़ के पास रास्ते पर हुई, जो अभियुक्त बटू की ज़मीन पर खड़ा था। पिटाई करने के बाद अभियुक्त पूरब की ओर भाग गए। रक्षपाल ज़मीन पर गिर गया था। उसने पूरी घटना 25-30 कदम की दूरी से देखी और जब अभियुक्त भाग जाने के बाद वह रक्षपाल के पास गया, तो उसने पाया कि उसकी मौत हो चुकी थी। उसने सोरन (पी.डब्ल्यू.-2) और लाले के शरीर पर भी चोटें देखीं। फिर उसने रक्षपाल को एक चारपाई पर अपने घरे में रखवाया और फिर घायल सोरन और लाले को एक इनलप गाड़ी में बिठाकर थाना कुरफतेहगढ़ ले गया। पुलिस स्टेशन जाते समय, उसने धूम नगर गाँव के राजेंद्र नाम के एक व्यक्ति से लिखित रिपोर्ट (प्रदर्श क-1) लिखवाई, जिसे वह अपने साथ ले गया और पुलिस स्टेशन में दर्ज करवाया।

11. विवेचना अधिकारी, उपनिरीक्षक एस.के. सागर (पी.डब्ल्यू.5) ने गवाही दी कि यह जांच उन्हें सौंपी गई थी और वे उसी दिन दोपहर 3.10 बजे घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने तुरंत ही शव-जांच की कार्यवाही शुरू कर दी, जिसे उन्होंने शाम 5 बजे तक पूरा कर लिया। यह बात शव-जांच रिपोर्ट (प्रदर्श क-4) से भी साबित होती है। बाबू सिंह (डी.डब्ल्यू.1) ने एक जगह यह बयान दिया कि सब-इंस्पेक्टर दोपहर 1.30 बजे ही घटनास्थल पर पहुंच गए थे, और फिर वे वापस चले गए और रक्षपाल के शव के संबंध में पंचायतनामा तैयार करने के लिए दोबारा लौटे। उनके इस बयान की पुष्टि किसी अन्य सबूत से नहीं हुई है कि S.I. दोपहर 1.30 बजे घटनास्थल पर पहुंचे थे और फिर वापस चले गए थे। यदि यह सच होता, तो अभियोजन पक्ष के गवाहों से इस संबंध में अवश्य ही पूछताछ की गई होती। घटना स्वयं दोपहर 1:00 बजे हुई थी, और जब तक पुलिस को इसकी सूचना नहीं मिलती, वह इतनी जल्दी घटनास्थल पर नहीं पहुंच सकती थी। इस प्रकार, अभियोजन पक्ष का यह दावा कि पुलिस दोपहर 3.10 बजे घटनास्थल पर पहुंची, सही प्रतीत होता है। घटनास्थल पर विवेचना अधिकारी ने फोटो नाश, चालान नाश और अन्य आवश्यक दस्तावेज तैयार किए। शव को सील कर दिया गया और फिर कांस्टेबलों के माध्यम से पोस्टमार्टम जांच के लिए भेज दिया गया। जैसा कि चालान नाश (प्रदर्श क-6) से पता चलता है, शव अगले दिन, यानी 24.6.84 को सुबह 7.15 बजे मुख्यालय स्थित पुलिस लाइंस पहुंच गया था; और जैसा कि पोस्टमार्टम जांच रिपोर्ट (प्रदर्श क-16) से पता चलता है, डॉक्टर ने उक्त पोस्टमार्टम जांच 24.6.84 को ही दोपहर 3.10 बजे की थी। विवेचना अधिकारी (पी.डब्ल्यू.5) की गवाही से यह भी स्पष्ट होता है कि उन्होंने सूचनादाता, यानी सावले (पी.डब्ल्यू.1) से शाम 5.30 बजे पूछताछ की थी।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



घटना वाले दिन ही, और यह कि उसने अगले दिन सोरन (पी.डब्ल्यू.2) और लाले से पूछताछ की। सोरन (पी.डब्ल्यू.-2) की गवाही में यह बात सामने आई है कि वह मेडिकल जांच के लिए गया था और फिर उस रात शव के साथ ही रहा, और इसलिए घटना वाले दिन वह गांव में मौजूद नहीं था।

12. ऊपर चर्चा किए गए सबूतों से यह साबित होता है कि विचाराधीन घटना 23.6.84 को दोपहर 1 बजे, मृतक और अभियुक्त बट्टू के घरों के बीच के रास्ते पर हुई थी।

13. पूर्वोक्त साक्ष्य से यह भी पता चलता है कि इस घटना में मृतक रक्षपाल, सोरन (पी.डब्ल्यू.2) और लाले को चोटें आईं, और रक्षपाल की मौके पर ही मृत्यु हो गई। जाँच अधिकारी (पी.डब्ल्यू.6) की गवाही से यह भी पता चलता है कि उन्होंने 23.6.84 को ही दोपहर 3.10 बजे से शाम 5 बजे के बीच पंचायतनामा (प्रदर्शक-4) तैयार किया, और शव को सीलबंद कपड़े में रखने के बाद उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। यह पोस्टमार्टम डॉ. एन.के. गुप्ता द्वारा 24.6.84 को दोपहर 3.10 बजे किया गया। डॉ. गुप्ता ने पाया कि ऊपरी अंगों में 'रिगर मॉर्टिस' (शरीर का अकड़ना) समाप्त हो चुका था, लेकिन निचले अंगों में यह अभी भी मौजूद था। उन्होंने निम्नलिखित 'एंटी-मॉर्टिस' (मृत्यु-पूर्व) चोटें पाई :-

- i. सीने के बाईं ओर, बाएं निप्पल से 8 सेमी. की दूरी पर, 2 सेमी. x 1/2 सेमी. का गोल छेद वाला घाव।
- ii. बाएं कंधे के जोड़ पर, बाएं कोहनी के जोड़ से 22 1/2 सेमी. ऊपर, 1 सेमी. x 1 सेमी. का गोल छेद वाला घाव।
- iii. बाएं हाथ के पिछले हिस्से पर, बाएं कंधे के जोड़ से 4 सेमी. नीचे, 2 सेमी. x 1 सेमी. का फटा हुआ घाव।
- iv. बाएं हाथ की छोटी उंगली पर 2 सेमी. x 4 सेमी. का खरोंच का निशान।

14. डॉक्टर की राय में, रक्षपाल की मौत ऊपर बताई गई चोटों के कारण हुए सदमे और रक्तस्राव से हुई थी। उनकी राय में, जांच से एक दिन पहले ही मौत हो चुकी थी।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



15. पोस्टमार्टम जांच रिपोर्ट (प्रदर्श क-16) की प्रामाणिकता को बचाव पक्ष ने स्वीकार कर लिया है। बचाव पक्ष ने सोरन और लाले की जांच से संबंधित चोट रिपोर्ट (प्रदर्श क-17 और का-18) की प्रामाणिकता को भी स्वीकार किया है।

16. चोट रिपोर्ट (प्रदर्श क-18) से पता चलता है कि लाले उर्फ लाल सिंह की जांच 23.6.84 को सुबह 9.15 बजे पी.एच.सी. कुंदिरकी में ही की गई थी, और इसमें निम्नलिखित चोटें पाई गईं:-

i. सिर के दाहिने तरफ 5 सेमी. x 2 सेमी. x खोपड़ी की गहराई तक एक फटा हुआ घाव, जो दाहिने कान और दोनों भौहों से 13 सेमी. की दूरी पर था; जमा हुआ खून दिखाई दिया और धोने पर घाव से खून बहने लगा।

ii. सिर के पिछले हिस्से के दाहिने तरफ 2 सेमी. x .2 सेमी. x 2 सेमी. के फटे हुए घाव, जो दाहिने कान से 11 सेमी. ऊपर और चोट संख्या 1 से 4 सेमी. पीछे थे; धोने पर खून बहने लगा; जमा हुआ खून मौजूद था।

iii. सीने के दाहिने तरफ 3 सेमी. x .3 सेमी. x 2 सेमी. का एक फटा हुआ घाव, जो दाहिने निप्पल से 7 सेमी. और दाहिनी कांख से 18 सेमी. की दूरी पर था; घाव पर जमा हुआ खून मौजूद था।

iv. दाहिनी बांह के बाहरी हिस्से पर 2 सेमी. x 1 सेमी. का एक नीलगू, जो कोहनी के जोड़ के ठीक ऊपर था; रंग लाल था।

v. बाईं कलाई के जोड़ से 9 सेमी. ऊपर, बाईं बांह के अगले हिस्से पर 3 सेमी. x .3 सेमी. का एक खरोंच; जमा हुआ खून मौजूद था।

17. डॉक्टर की राय में, सभी चोटें किसी कुंद चीज़ से लगी थीं, वे मामूली किस्म की थीं, और जाँच के समय वे लगभग आधे दिन पुरानी थीं।

18. चोट रिपोर्ट (प्रदर्श क-17) से पता चलता है कि सोरन (पी.डब्ल्यू.2) की जाँच 23.6.84 को रात 9.30 बजे की गई थी, और उसके शरीर पर मिली चोटें इस प्रकार हैं:

i. सिर के बाईं ओर, बाएं कान से 11 सेमी. ऊपर और बाईं भौंह से 8 सेमी. ऊपर, 6.5 सेमी. x 0.7 सेमी. x सिर की त्वचा की गहराई तक कटा हुआ घाव; जमा हुआ खून दिखाई दिया और धोने पर घाव से खून बहने लगा।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



ii. माथे के बाईं ओर, बाईं भौंह से 3 सेमी. ऊपर, 2 सेमी. x 2 सेमी. का खरोंच का निशान; घाव से सीरम (तरल पदार्थ) निकल रहा था।

iii. दाहिने कान के बाहरी हिस्से (पिन्ना) के बीच में, 4 सेमी. x 0.3 सेमी. x 0.5 सेमी. का कटा हुआ घाव, जिसने कान के बाहरी हिस्से को दो भागों में बांट दिया था; यह घाव अंदर की ओर 2 सेमी. x 3 सेमी. x 0.5 सेमी. तक फैला हुआ था; जमा हुआ खून दिखाई दिया, जो धोने पर बहने लगा।

iv. दाहिनी बांह के पिछले और बाहरी हिस्से पर, दाहिनी कोहनी के जोड़ के ठीक ऊपर, 2 सेमी. x 1 सेमी. का खरोंच का निशान; जमा हुआ खून दिखाई दिया।

v. दाहिने पैर के ऊपरी हिस्से के बीच में, 1 सेमी. x 1 सेमी. का खरोंच का निशान; जमा हुआ खून दिखाई दिया।

vi. बाएं घुटने के जोड़ के निचले और सामने के हिस्से पर, 2 सेमी. x 1 सेमी. का खरोंच का निशान; जमा हुआ खून दिखाई दिया।

vii. गर्दन के निचले दाहिने हिस्से के बाहरी भाग पर, इलियक क्रेस्ट (कूल्हे की हड्डी के ऊपरी किनारे) के ठीक ऊपर, 13 सेमी. x 3 सेमी. का नील (चोट का निशान); रंग लाल था।

viii. पीठ के दाहिने हिस्से पर, चोट संख्या 7 से 4 सेमी. ऊपर, 13 सेमी. x 3 सेमी. का लंबवत नील; रंग लाल था।

18. डॉक्टर की राय में, सभी चोटें साधारण थीं और किसी कठोर, कुंद वस्तु से लगी थीं; जाँच के समय ये चोटें लगभग आधे दिन पुरानी थीं।

19. अपीलकर्ताओं के बयान दं.प्र.सं. की धारा 313 के तहत दर्ज किए गए। दं.प्र.सं. की धारा 313 के तहत दर्ज अपीलकर्ताओं के बयान में, अभियुक्त-अपीलकर्ता संख्या 1, बट्टू सिंह ने प्रश्न संख्या 18 के उत्तर में कहा कि लाले, सोरन और रक्षपाल ने उस पर हमला किया था, और उसने लाठी से अपना बचाव किया, जिससे उसे चोटें आईं। अपीलकर्ता संख्या 7, मुंशी जी ने भी कहा कि सोरन, लाले और रक्षपाल ने उस पर हमला किया था, और उसने लाठी का इस्तेमाल करके अपना बचाव किया, जिससे उसे भी चोटें आईं।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



20. डी.डब्ल्यू.-1, डॉ. ए.के. महेन्द्र ने यह साबित किया कि 27.6.2018 को, उन्होंने मृतक अपीलकर्ता संख्या 5, दीना (बृजपाल का पुत्र) की जाँच की और उसके दाहिने सीने तथा बाएं अंगूठे के अंदरूनी हिस्से पर दो फटे हुए घाव पाए। यह चिकित्सकीय जाँच उन्होंने जेल में की थी। उन्होंने अभियुक्त बट्टू सिंह की भी जाँच की, जिसके बाएं पैर पर खरोंचें और नील के निशान थे, और उसके घुटने पर भी खरोंचें थीं। उसे पीठ के बाएं हिस्से और सिर के निचले हिस्से पर भी चोटें आई थीं। इसके बाद उन्होंने अपीलकर्ता संख्या 7, मुंशी जी की जाँच किया और उनके हाथ, घुटनों और पैरों पर पाँच चोटें पाईं। अंत में, उन्होंने मृतक अपीलकर्ता सतपाल की चोटों की जाँच की और उसके बाएं पैर पर नील का एक निशान पाया। सभी चोटें साधारण पाई गईं और संभवतः लाठी से लगी थीं।

21. अपीलकर्ता के अधिवक्ता ने यह दलील दी है कि यह मामला निजी बचाव के अधिकार के दायरे में आता है; अभियोजन पक्ष ने घटना की शुरुआत को छिपाया है, क्योंकि अभियोजन पक्ष ने अभियुक्तों को लगी चोटों के बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है; इस मामले में दं.प्र.सं. की धारा 157 के प्रावधानों का खुले तौर पर उल्लंघन किया गया है; विचारण न्यायालय ने भा.दं.सं. की धारा 99 उप-धारा (3) के प्रावधानों पर विचार नहीं किया; विचारण न्यायालय के सामने सभी अभियुक्तों की गैर-कानूनी भीड़ का होना, उचित संदेह से परे साबित नहीं हो सका; अभियुक्तों द्वारा लिए गए बचाव पक्ष के तर्कों और दं.प्र.सं. की धारा 313 के तहत दिए गए उनके बयानों पर विचारण न्यायालय ने विचार नहीं किया, और अपराध करने में कथित तौर पर इस्तेमाल किए गए किसी भी हथियार की कोई बरामदगी नहीं हुई।

22. शासकीय अधिवक्ता ने यह दलील दी है कि हत्या के मामले में निजी बचाव का तर्क नहीं दिया जा सकता; अभियुक्त घटना को अंजाम देने के लिए तैयार थे और शिकायतकर्ता पक्ष के पास सरकारी अधिकारियों को सूचित करने के लिए बिल्कुल भी समय उपलब्ध नहीं था; अभियुक्त पक्ष ही हमलावर थे और वे रास्ते पर अतिक्रमण कर रहे थे; गवाह पी.डब्ल्यू.-1 ने अपीलकर्ता संख्या 1, बट्टू सिंह को भाले से रक्षपाल को चोट पहुंचाने की भूमिका सौंपी है, जबकि अपीलकर्ता संख्या 7 और अपीलकर्ता संख्या 11 को लाठियों से बृजपाल, रक्षपाल, सोमली और दीना को चोट पहुंचाने की भूमिका सौंपी है। गवाह पी.डब्ल्यू.-2 ने बट्टू सिंह द्वारा भाले से मेहरबान को चोट पहुंचाने की भूमिका सौंपी है, और अपीलकर्ता संख्या 7 तथा अपीलकर्ता संख्या 11 द्वारा लाठियों से चोट पहुंचाने की भूमिका सौंपी है। गवाह पी.डब्ल्यू.-3 ने भी अपीलकर्ताओं को यही भूमिका सौंपी है; चूंकि अपीलकर्ताओं को विशिष्ट भूमिकाएं सौंपी गई थीं, इसलिए विचारण न्यायालय ने “अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



उन्हें सही तौर पर दोषी ठहराया है और सज़ा सुनाई है; विचारण न्यायालय ने गवाह डी.डब्ल्यू.-2 के बयान को विश्वसनीय नहीं पाया, और अभियुक्तों द्वारा अपनी गैर-मौजूदगी का कोई तर्क भी पेश नहीं किया गया। शासकीय अधिवक्ता(ने सर्वोच्च न्यायालय के उन निर्णयों का हवाला दिया है, जो *राम रतन और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (एआईआर1977एससी619)*, *जगमाल सिंह और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2008 (61) एससीसी 820)*, और *हुकुम सिंह और अन्य बनाम... के मामलों में दिए गए थे। अपने तर्कों के समर्थन में, स्टेट ऑफ़ यू.पी., एआईआर 1959 इला 690।*

23. पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत विरोधी दलीलों को सुनने के बाद, और अभिलेख पर मौजूद सामग्री तथा विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और आदेश का अवलोकन करने पर, हम पाते हैं कि अभियोजन पक्ष के मामले के अनुसार, सुबह लगभग 11:00 बजे, सावले (पी.डब्ल्यू.-1) की पत्नी उसके और उसके भाइयों के लिए खाना लेकर आई। वे सभी खेत में काम कर रहे थे। पत्नी ने उन्हें बताया कि अभियुक्त लोग पी.डब्ल्यू.-1 की तरफ से मिट्टी उठाकर अपनी तरफ ले जा रहे हैं। पी.डब्ल्यू.-1 अपना काम करता रहा और कहा कि वह बाद में उन्हें देख लेगा। इसलिए, अभियोजन पक्ष के अपने ही मामले से यह स्पष्ट है कि अभियुक्त पक्ष अभियोजन पक्ष की संपत्ति के विरुद्ध अपराध कर रहा था, और इसलिए, अभियोजन पक्ष ने अपनी संपत्ति के अधिकारों की रक्षा करने का प्रयास किया, जिसके परिणामस्वरूप विवादित घटना घटित हुई।

24. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने अपनी इस दलील पर बहुत ज़ोर दिया है कि अभियोजन पक्ष के पास उन अभियुक्तगण के विरुद्ध 'निजी बचाव' का कोई अधिकार नहीं हो सकता, जिन्होंने स्वयं अपने निजी बचाव के अधिकार का प्रयोग किया था; जैसा कि उन्हें लगी चोटों से स्पष्ट है, जिनकी जांच जेल डॉक्टर द्वारा की गई थी और जिन्हें साबित भी किया गया था। उन्होंने यह तर्क दिया है कि किसी भी कार्य के विरुद्ध निजी बचाव का अधिकार तब नहीं हो सकता, जब सार्वजनिक अधिकारियों से सुरक्षा प्राप्त करने का समय उपलब्ध हो, जैसा कि भा.दं.सं. की धारा 99 के उप-खंड (3) में बताया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि पी.डब्ल्यू.-1 की पत्नी ने सुबह 11:00 बजे पी.डब्ल्यू.-1 को सूचना दी थी कि अभियुक्त लोग उनकी तरफ से मिट्टी उठाकर अपनी तरफ जमा कर रहे हैं, लेकिन पी.डब्ल्यू.-1 ने कुछ नहीं किया, और विवादित घटना दोपहर 01:00 बजे घटित हुई। इसलिए, यह स्पष्ट है कि पी.डब्ल्यू.-1 के पास सुबह 11:00 बजे से दोपहर "अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



01:00 बजे तक, यानी दो घंटे का समय था, जिसमें वह अभियुक्तगण के विरुद्ध सार्वजनिक अधिकारियों से शिकायत कर सकता था; लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। अतः, अभियोजन पक्ष अपनी संपत्ति की रक्षा के लिए 'निजी बचाव' की दलील नहीं ले सकता, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को निजी बचाव का अधिकार केवल भा.दं.सं. की धारा 99 के उप-खंड (3) में निहित शर्तों के अधीन ही प्राप्त होता है। त्वरित संदर्भ के लिए, भा.दं.सं. की धारा 99 का उप-खंड (3) यहाँ नीचे उद्धृत किया जा रहा है:-

"ऐसे मामलों में निजी बचाव का कोई अधिकार नहीं होता, जहाँ सार्वजनिक अधिकारियों से सुरक्षा पाने के लिए समय उपलब्ध हो।"

25. विचार का दूसरा बिंदु यह है कि घटना अभियुक्त-अपीलकर्ता संख्या 1, बटू की ज़मीन पर बने रास्ते (पैसेज) पर हुई थी। इसलिए, ऐसा प्रतीत होता है कि अभियोजन पक्ष ही हमलावर था और वह अभियुक्त की ज़मीन पर गया तथा वहीं घटना को अंजाम दिया। इस संबंध में, अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने 'लखन और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य' (2025:एचसी:69540-डीबी) के निर्णय की मदद लिया है, जिसमें निम्नलिखित बात कही गई है:

"अभिलेख पर रखे गए तथ्यों और प्रस्तुत तर्कों पर विचार करने के बाद, यह आभास होता है कि, भले ही अपीलकर्ताओं के विरुद्ध लगाए गए आरोपों को सत्य मान लिया जाए, फिर भी वे 'निजी बचाव के अधिकार' के आधार पर दोषमुक्ति के हकदार हैं। अभियोजन पक्ष का यह स्वीकारोक्तिपूर्ण मामला है कि प्राण, विक्रमा तालाब से स्नान करके लौट रहा था, और जब वह अपीलकर्ताओं के घर के सामने पहुँचा, तब यह घटना घटित हुई। इसलिए, अभियोजन पक्ष ही हमलावर था। जब अपीलकर्ताओं ने देखा कि देशराज पर हमला किया जा रहा है, तो उन्होंने अपने 'निजी बचाव के अधिकार' का प्रयोग करते हुए प्राण और बीच-बचाव करने वाले अन्य सभी लोगों पर हमला किया। यद्यपि, विचारण न्यायालय ने बचाव पक्ष के तर्कों पर ध्यान दिया था, किंतु उसने उन पर कोई चर्चा नहीं की। विचारण न्यायालय ने न तो बचाव पक्ष के गवाहों, न ही बचाव पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों, और न ही बचाव पक्ष को लगी चोटों के संबंध में कोई टिप्पणी की है। अभियोजन पक्ष के गवाहों ने अपनी गवाही में, बचाव पक्ष को लगी चोटों के बारे में कुछ भी उजागर नहीं किया, और न ही उन्होंने घटना के मूल कारण का खुलासा किया। यद्यपि उन्होंने घटना के बारे में बयान दिया था, किंतु इन पहलुओं पर वे पूरी तरह से मौन रहे। बचाव पक्ष ने अपनी चोटों को सिद्ध

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



कर दिया है, जो उसी घटना के दौरान लगी थीं। इस प्रकार, अभियोजन पक्ष ने घटना के मूल कारण और उसकी उत्पत्ति को छिपाया है, और अभियुक्त के शरीर पर लगी चोटों की व्याख्या करने में विफल रहा है; अतः, अभियोजन पक्ष के विरुद्ध एक प्रतिकूल निष्कर्ष निकाला जा सकता है, क्योंकि उसने कोई स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया—और एक विश्वसनीय स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने की तो बात ही दूर है। अभियोजन पक्ष ने घटना का वास्तविक विवरण अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं किया है; इसलिए, इस मामले की विफलता के लिए उसे स्वयं ही पूर्ण रूप से दोषी ठहराया जाना चाहिए।"

26. विचार करने लायक अगला बिंदु दं.प्र.सं. की धारा 157 के प्रावधानों के पालन से संबंधित है। हेड कांस्टेबल, बृजभान सिंह (पी.डब्ल्यू.-4) ने अपनी जिरह में यह स्वीकार किया है कि उन्होंने की प्रति मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को कभी नहीं भेजी, क्योंकि उसे भेजने की आवश्यकता नहीं थी। हमने पाया कि सर्वोच्च न्यायालय ने **'अर्जुन मारिक और अन्य बनाम बिहार राज्य, 1994 सप्लीमेंट्री (2) एससीसी 372** वाद में यह अभिनिर्धारित किया है कि मजिस्ट्रेट को एफआईआर भेजने में केवल देरी होने से ही अभियोजन पक्ष का मामला कमजोर हो जाता है; लेकिन इस मामले में यह स्वीकार किया गया है कि पी.डब्ल्यू.-4 द्वारा संबंधित मजिस्ट्रेट को एफआईआर कभी भेजी ही नहीं गई, और इसलिए अभियोजन पक्ष की कहानी अत्यंत संदिग्ध हो जाती है।

27. अभियुक्त को लगी चोटों के बारे में पी.डब्ल्यू.-1, पी.डब्ल्यू.-2 या पी.डब्ल्यू.-3 में से किसी ने भी कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया; उन्होंने तो बस यही इनकार किया कि उन्होंने अभियुक्त को कोई चोट नहीं पहुँचाई थी। परंतु डी.डब्ल्यू.-1, डॉ. ए.के. महेंद्र—जिन्होंने जेल में अभियुक्त की जाँच की थी—ने यह सिद्ध कर दिया कि अभियुक्त को कथित घटना के दिनांक और समय के आसपास ही चोटें लगी थीं; और इसलिए, इस आधार पर भी अभियोजन पक्ष का मामला संदिग्ध हो जाता है।

28. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **राजस्थान राज्य बनाम माधो और अन्य (एआईआर 1991 एससी 1065)** वाद में यह टिप्पणी की थी कि:

"यदि अभियोजन पक्ष के गवाह सच्चाई से कतराते हैं और प्रत्यर्थियों को लगी चोटों के बारे में स्पष्टीकरण नहीं देते हैं, तो इससे अभियोजन पक्ष के मामले की बुनियाद पर ही संदेह पैदा हो

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



जाता है, क्योंकि सबूतों से यह पता चलता है कि ये चोटें उसी घटना के दौरान लगी थीं। इससे यह आभास होता है कि गवाह घटना के किसी हिस्से को छिपा रहे हैं।"

29. **लक्ष्मी सिंह और अन्य बनाम बिहार राज्य ((1976) 4 एससीसी 394)** वाद में माननीय सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणियों का संदर्भ देते हुए, जिसमें यह कहा गया था कि:

"12..... हमें ऐसा प्रतीत होता है कि हत्या के किसी मामले में, घटना के समय या कहा-सुनी (झगड़े) के दौरान अभियुक्त को लगी चोटों के बारे में स्पष्टीकरण न देना एक बहुत ही महत्वपूर्ण परिस्थिति है, जिससे न्यायालय निम्नलिखित निष्कर्ष निकाल सकता है:

"(1) कि अभियोजन पक्ष ने घटना की शुरुआत और उसके मूल को छिपाया है, और इस प्रकार घटना का सही विवरण प्रस्तुत नहीं किया है:

(2) कि जिन गवाहों ने अभियुक्त के शरीर पर चोटों की मौजूदगी से इनकार किया है, वे एक अत्यंत महत्वपूर्ण बिंदु पर झूठ बोल रहे हैं, और इसलिए, उनकी गवाही अविश्वसनीय है:

(3) कि यदि बचाव पक्ष की ओर से कोई ऐसा विवरण प्रस्तुत किया जाता है जो अभियुक्त के शरीर पर मौजूद चोटों की व्याख्या करता हो, तो वह विवरण इतना विश्वसनीय माना जाएगा कि उससे अभियोजन पक्ष के मामले पर संदेह उत्पन्न हो जाए।"

30. हाल ही में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने '**नंद लाल और अन्य बनाम छत्तीसगढ़ राज्य**' (2023) 2 एससीआर 276 वाद में, ऊपर संदर्भित टिप्पणियों को दोहराते हुए, निम्नलिखित निर्णय दिया:

"अभियोजन पक्ष द्वारा अभियुक्त के शरीर पर मौजूद चोटों की व्याख्या करने में की गई चूक का महत्व तब और भी अधिक बढ़ जाता है, जब गवाही देने वाले गवाह 'हितबद्ध' या 'शत्रुतापूर्ण' हों; अथवा जब बचाव पक्ष की ओर से प्रस्तुत किया गया विवरण, अभियोजन पक्ष के विवरण की तुलना में अधिक विश्वसनीय प्रतीत होता हो—विशेष रूप से तब, जब कुछ गवाहों ने यह कहकर झूठ बोला हो कि उन्होंने अभियुक्त के शरीर पर किसी भी प्रकार की चोट नहीं देखी।"

इस प्रकार, अभियुक्तों के शरीर पर लगी चोटों के बारे में कोई स्पष्टीकरण न देना, इस बात पर संदेह पैदा करता है कि क्या अभियोजन पक्ष ने घटना की असली वजह को अभिलेख पर लाया है। हालाँकि, इस तरह का स्पष्टीकरण न देना एक ऐसा कारक है जिसे अभियोजन पक्ष के गवाहों

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



की विश्वसनीयता को परखते समय ध्यान में रखा जाना चाहिए, और न्यायालय को साक्ष्यों की सावधानीपूर्वक जाँच करनी चाहिए। प्रत्येक मामले की अपनी विशिष्टताएँ होती हैं। कुछ मामलों में, अभियोजन पक्ष द्वारा अपनी कहानी के संदर्भ में चोटों का स्पष्टीकरण न दे पाना एक कमी हो सकती है, जबकि अन्य मामलों में इसका अभियोजन पक्ष के मामले पर बहुत कम या कोई भी प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ सकता है। किसी विशेष मामले में, यह एक ऐसे सार्वभौमिक रूप से लागू होने वाले कानूनी सिद्धांत के पक्ष को भी मजबूत कर सकता है, जिसके अनुसार जैसे ही यह पाया जाता है कि अभियुक्त को उसी घटनाक्रम में चोटें लगी थीं जिसमें शिकायतकर्ता पक्ष पर हमला किया गया था, तो 'निजी बचाव' का दावा प्रथम दृष्टया स्थापित माना जाएगा; और तब यह साबित करने का दायित्व अभियोजन पक्ष पर आ जाएगा कि वे चोटें शिकायतकर्ता पक्ष द्वारा आत्मरक्षा में अभियुक्त को पहुँचाई गई थीं।

31. अब, भा.दं.सं. की धारा 149 की मदद से अभियुक्त की संलिप्तता पर विचार करना ज़रूरी है। संहिता की धारा 149 'सामान्य उद्देश्य' से संबंधित है। इस प्रावधान को लागू करने के लिए, कम से कम पाँच व्यक्तियों के एक समूह के होने का सबूत होना चाहिए, जिनका सामान्य उद्देश्य अवैध हो। 'रचनात्मक' या 'प्रतिनिधिक दायित्व' की अवधारणा इस प्रावधान में तब लाई जाती है, जब गैर-कानूनी समूह के किसी एक सदस्य द्वारा किया गया अपराध, उस समूह के अन्य सदस्यों पर भी लागू होता है, जिनका उद्देश्य भी वही सामान्य उद्देश्य था। यह 'सामान्य उद्देश्य' की साझेदारी ही है, जिसके कारण एक सदस्य द्वारा किया गया अपराध, समूह के अन्य सदस्यों पर भी लागू हो जाता है। इसलिए, किसी समूह में केवल उपस्थित होना अपने आप में कोई अपराध नहीं है; यह अपराध तब बनता है, जब वह समूह 'गैर-कानूनी' हो। अपराध करने का जो 'सामान्य उद्देश्य' होता है, उसी के परिणामस्वरूप वह अपराध घटित होता है। इसलिए, भले ही अपराध किसी एक व्यक्ति द्वारा किया गया हो, लेकिन एक 'मानक कल्पना' के आधार पर इसे अन्य सदस्यों पर भी लागू मान लिया जाता है, क्योंकि अपराध करने के उनके उद्देश्य में समानता होती है। इस प्रकार, यह अभियोजन पक्ष का दायित्व है कि वह उन तथ्यों को साबित करे, जैसे— समूह का अस्तित्व (जिसमें आवश्यक संख्या में सदस्य हों), सभी सदस्यों का एक 'सामान्य उद्देश्य' होना, उस उद्देश्य का गैर-कानूनी होना, और समूह के किसी एक सदस्य द्वारा वास्तव में कोई अपराध किया जाना। भा.दं.सं. की धारा 149 के तहत अभियुक्त पर आरोप तय करते समय, न्यायालयों को अधिक सतर्क और सावधान रहना होगा, क्योंकि इस धारा में एक 'मानक

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



कल्पना' शामिल है। इसलिए, अभियोजन पक्ष पर यह साबित करने का दायित्व अधिक होता है कि जिस व्यक्ति पर अपराध का आरोप है, वह भा.दं.सं. की धारा 149 के तहत, समूह के अन्य सदस्यों द्वारा किए गए अपराध के लिए भी दंड का भागीदार है। उपरोक्त पहलू से संबंधित सिद्धांत को सर्वोच्च न्यायालय ने 'रणजीत सिंह बनाम पंजाब राज्य' [(2013) 15 एससीसी 752] के वाद में विचार में लिया था। 32. 'बलादीन बनाम उत्तर प्रदेश राज्य' [एआईआर 1956 एससी 181: 1956 क्रि0 एल.जे. 345] उन शुरुआती मामलों में से एक था, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने भा.दं.सं. की धारा 149 पर विचार किया था। न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि किसी समूह में केवल उपस्थित होने मात्र से कोई व्यक्ति 'गैर-कानूनी समूह' का सदस्य नहीं बन जाता; जब तक कि यह साबित न हो जाए कि उसने ऐसा कोई कार्य किया है (या कोई कार्य करने से जानबूझकर विरत रहा है), जिससे यह स्पष्ट हो कि वह उस गैर-कानूनी समूह का सदस्य था—अथवा जब तक कि वह मामला भा.दं.सं. की धारा 142 के अंतर्गत न आता हो।

नतीजतन, अगर किसी परिवार के सभी सदस्य और गाँव के दूसरे निवासी घटना वाली जगह पर इकट्ठा हो गए थे, तो ऐसे सभी लोगों को अपने आप गैर-कानूनी जमावड़े का सदस्य नहीं माना जा सकता। ऐसे सभी मामलों में, अभियोजन पक्ष को यह साबित करने के लिए सबूत पेश करने होंगे कि किसी खास अभियुक्त ने कोई ऐसा काम किया था जिससे यह साबित हो सके कि वह गैर-कानूनी जमावड़े का सदस्य था। इसके लिए हर व्यक्ति के मामले की जाँच करना ज़रूरी होगा, ताकि जो लोग सिर्फ तमाशबीन थे और जो बस जमावड़े में शामिल हो गए थे और जिन्हें इसके मकसद के बारे में पता नहीं था, उन्हें गैर-कानूनी जमावड़े का सदस्य न मान लिया जाए।

33. बालादीन मामले [एआईआर 1956 एससी 181: 1956 क्रि0एलआई 345] में की गई टिप्पणियों पर मसाल्टी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य [एआईआर 1965 एससी 202: (1965) 1 क्रि0एलजे 226] वाद में विचार किया गया, जहाँ इस न्यायालय ने समझाया कि जिन मामलों में लोग सिर्फ मूक गवाह थे और जो सिर्फ जिज्ञासावश जमावड़े में शामिल हुए थे, और जिनका जमावड़े के आम मकसद से कोई लेना-देना नहीं था, उनके मामले अलग थे; अन्यथा, यह साबित करना ज़रूरी नहीं था कि उस व्यक्ति ने कोई गैर-कानूनी काम किया था या जमावड़े के आम मकसद को पूरा करने में उससे कोई चूक हुई थी, इससे पहले कि उसे भा.दं.सं. की धारा 149 की मदद से जमावड़े के किसी दूसरे सदस्य द्वारा किए गए काम के नतीजों के लिए ज़िम्मेदार ठहराया जा सके। इस

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



संबंध में नीचे दिया गया अंश प्रासंगिक है: (मसाल्टी मामला [एआईआर 1965 एससी 202: (1965) 1 क्रि0एलजे 226], एआईआर पृष्ठ 211, पैरा 17)

"17.... ऐसे मामले में तय करने वाला अहम सवाल यह है कि क्या उस जमावड़े में पाँच या उससे ज्यादा लोग थे और क्या उन लोगों का कोई एक या ज्यादा ऐसा साझा मकसद था, जैसा कि धारा 141 में बताया गया है। इस सवाल को तय करते समय, यह देखना ज़रूरी हो जाता है कि क्या उस जमावड़े में कुछ ऐसे लोग भी थे जो सिर्फ मूक दर्शक थे और उस जमावड़े के साझा मकसद को पूरा करने के इरादे से उसमें शामिल नहीं हुए थे। इसी संदर्भ में, इस न्यायालय की ओर से 'बलादीन' [एआईआर 1956 एससी 181: 1956 क्रि0एलजे 345] मामले में की गई टिप्पणियाँ अहम हो जाती हैं—कि कोई व्यक्ति सिर्फ अपनी जिज्ञासा शांत करने के लिए किसी जमावड़े में शामिल हो सकता है, न कि उस जमावड़े के साझा मकसद को पूरा करने के इरादे से। वरना, कानून की नज़र में, यह कहना सही नहीं होगा कि किसी व्यक्ति को किसी गैर-कानूनी जमावड़े का सदस्य मानने से पहले, यह साबित करना ज़रूरी है कि उसने उस जमावड़े के साझा मकसद को पूरा करने के लिए कोई गैर-कानूनी काम किया हो या किसी गैर-कानूनी काम को जान-बूझकर न किया हो। असल में, धारा 149 यह साफ़ करती है कि अगर किसी गैर-कानूनी जमावड़े का कोई सदस्य, उस जमावड़े के साझा मकसद को पूरा करने के दौरान कोई अपराध करता है—या ऐसा कोई अपराध करता है जिसके बारे में उस जमावड़े के सदस्यों को पता था कि उस मकसद को पूरा करने के दौरान ऐसा अपराध होने की संभावना है—तो उस अपराध के होने के समय उस जमावड़े का जो भी सदस्य वहाँ मौजूद होगा, वह हर व्यक्ति उस अपराध का दोषी माना जाएगा। और यह बात ज़ोर देकर उस सिद्धांत को सामने लाती है कि धारा 149 के तहत दी जाने वाली सज़ा, एक तरह से 'प्रतिनिधिक' होती है; यानी यह हमेशा इस आधार पर नहीं दी जाती कि वह अपराध गैर-कानूनी जमावड़े के हर सदस्य ने खुद किया हो।"

(प्रभाव वर्धित)

34. पुनः, **बाजवा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य ((1973) 1 एससीसी 714)** वाद में, सर्वोच्च न्यायालय ने यह माना कि गुटों में बंटे समाज में, अक्सर यह प्रवृत्ति होती है कि निर्दोष लोगों को भी दोषियों के साथ फंसा दिया जाए; ऐसे में, निर्दोषों को दोषियों के साथ दंडित किए जाने के जोखिम से

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



बचने का एकमात्र उपाय यह है कि ऐसे स्वीकार्य साक्ष्यों पर ज़ोर दिया जाए जो किसी हद तक अभियुक्त को अपराध से जोड़ते हों और न्यायालय की अंतरात्मा को संतुष्ट करते हों।

35. गुटों में बंटे ग्रामीण समुदायों में, दोषियों के साथ-साथ निर्दोष लोगों को भी फंसाने की प्रवृत्ति होती है—विशेषकर तब, जब किसी अपराध को अंजाम देने में बड़ी संख्या में हमलावर शामिल हों; यह एक सर्वविदित तथ्य है। ऐसे मामलों में साक्ष्य का पक्षपातपूर्ण होना स्वाभाविक है; हालाँकि, न्यायालय केवल इसी आधार पर ऐसे साक्ष्यों को सिरे से खारिज करने का आसान रास्ता नहीं अपना सकते। इसके बजाय, उन्हें गवाहों के बयानों को सावधानीपूर्वक देखना चाहिए और साक्ष्यों की अधिक बारीकी से जाँच करनी चाहिए, ताकि न्याय की किसी भी प्रकार की विफलता से बचा जा सके।

36. अंततः, हमने पाया कि अपराध में प्रयुक्त हथियारों—अर्थात् भाला और लाठियों—में से कोई भी बरामद नहीं हुआ; केवल एक फावड़ा बरामद हुआ। इस फावड़े का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि पी.डब्ल्यू.-2 (अभियोजन पक्ष के गवाह-2) ने स्वयं यह स्वीकार किया है कि कथित अपराध में फावड़े का उपयोग नहीं किया गया था।

37. **राम रतन (पूर्वोक्त)** वाद में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर एजीए का भरोसा सही नहीं है। पूर्वोक्त वाद में, शिकायतकर्ता, राम खेलावन ने एक चक रोड पर अतिक्रमण कर लिया था और उस पर फसलें बो दी थीं। जब अभियुक्त पक्ष ने ज़बरदस्ती अपने बैल उस अतिक्रमित चक रोड से निकालने की कोशिश की, तो दोनों पक्षों के बीच विवाद हो गया। सर्वोच्च न्यायालय ने यह माना कि शिकायतकर्ता, राम खेलावन, उस ज़मीन पर वास्तव में कब्ज़े में था—जो कि चक रोड थी—लेकिन उसे उस पर बोई गई अपनी फसलों की रक्षा करने का अधिकार था, और अभियुक्त पक्ष अपने बैल वहाँ से नहीं ले जा सकता था, क्योंकि राम खेलावन विवादित ज़मीन पर 'स्थिर कब्ज़े' में था। कानून का सहारा लिए बिना, उसकी फसलें नहीं हटाई जा सकती थीं। इसलिए, अभियुक्त द्वारा 'आत्म-रक्षा' के आधार पर दी गई दलील—कि वे जनता की संपत्ति, यानी चक रोड को खाली कराने की कोशिश कर रहे थे—को निचली न्यायालय, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय, तीनों ने ही स्वीकार नहीं किया।

38. **जगमाल सिंह (पूर्वोक्त)** का दूसरा निर्णय भी राज्य के लिए मददगार नहीं है, क्योंकि इसमें प्रस्तर 15 में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि असली मालिक को किसी घुसपैठिए को बेदखल

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



करने या बाहर निकालने का अधिकार तब होता है, जब घुसपैठिया घुसपैठ करने की क्रिया या प्रक्रिया में हो और उसने अभी तक अपना कब्ज़ा पूरी तरह से जमा न लिया हो। इस मामले में, जब अभियुक्त-अपीलकर्ताओं की तरफ से मिट्टी हटाई जा रही थी और यह काम पूरा होने वाला ही था, और पी.डब्ल्यू.-1 की पत्नी ने इसे सुबह 11:00 बजे देखा, और उसने इस बारे में पी.डब्ल्यू.-1 और उसके भाई को बताया, तो उन्होंने कुछ नहीं किया। दो घंटे बाद, वह घटना स्थल पर गया, जो अपीलकर्ताओं के घर के सामने था, और उसने लाठियों से अपीलकर्ताओं की तरफ हमला किया; इसके बाद अभियुक्त पक्ष ने अपने निजी बचाव के अधिकार का प्रयोग किया। घटना स्थल अपीलकर्ता संख्या 1, बट्टू के घर के सामने था, और इसलिए हमने पाया है कि अभियुक्त पक्ष ही हमलावर था। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि अभियोजन पक्ष के पास मदद के लिए सरकारी कर्मचारियों से संपर्क करने का अवसर था, लेकिन ऐसा करने के बजाय, उन्होंने कानून अपने हाथ में ले लिया, और तब अभियुक्त पक्ष ने उनके खिलाफ अपने निजी बचाव के अधिकार का प्रयोग किया।

39. इस वाद के तथ्यों और परिस्थितियों पर गहन विचार करने के बाद, हम पाते हैं कि यद्यपि अपीलकर्ताओं ने आत्मरक्षा के अपने अधिकार का प्रयोग किया, लेकिन अपीलकर्ता संख्या 1 ने अपने अधिकार की सीमा का उल्लंघन किया और मृतक को भाले से उसकी छाती में एक बार वार करके अत्यधिक चोट पहुँचाई। **रफ़ीक बनाम महाराष्ट्र राज्य 1979 एआईआर सर्वोच्च न्यायालय 1179 में प्रतिवेदित** के वाद में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय में यह अभिनिर्धारित किया गया था कि अपीलकर्ता आत्मरक्षा के अधिकार का प्रयोग करने का हकदार है, लेकिन अभिलेख पर मौजूद साक्ष्य, जो उसे लगी और उसे लगने की आशंका वाली चोटों की प्रकृति और गंभीरता को दर्शाते हैं, यह दिखाते हैं कि जब उसने मृतक के दिल में वार किया, तो उसने उस अधिकार की सीमा का उल्लंघन किया। उसने ऐसी चोट पहुँचाई जो गंभीर साबित हुई, और इसलिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उस मामले में यह अभिनिर्धारित किया कि अपीलकर्ता ने आत्मरक्षा के अपने अधिकार की सीमा का उल्लंघन किया।

40. वर्तमान वाद में भी, हम पाते हैं कि अपीलकर्ता ने आत्मरक्षा के अपने अधिकार की सीमा का उल्लंघन किया है। हम आगे यह भी पाते हैं कि पी.डब्ल्यू.-1 के बयान में यह बात सामने आई है कि अपीलकर्ता संख्या 1 (बट्टू) और मृतक-अपीलकर्ता संख्या 2 (मेहरबान) के हाथों में भाले थे।

बाकी अभियुक्तगण के पास लाठियाँ थीं। जबकि शिकायतकर्ता पक्ष केवल लाठियों से लैस था और “अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



उन्होंने अपीलकर्ता पक्ष पर लाठियों से वार किया था। अपीलकर्ता संख्या 1, बट्टू सिंह पर आरोप है कि उसने रक्षपाल पर भाले से वार किया, और मेहरबान पर भी आरोप है कि उसने रक्षपाल पर भाले से वैसा ही वार किया। मृतक, रक्षपाल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में, उसके शरीर पर केवल दो छिद्रित घाव पाए गए। एक उसकी छाती के बाईं ओर और दूसरा उसके बाएं कंधे के जोड़ पर था; इसके अलावा, उसके बाएं हाथ और बाएं हाथ की छोटी उंगली पर क्रमशः एक गहरा घाव और एक खरोंच भी थी। पी.डब्ल्यू.-1 द्वारा अपीलकर्ता संख्या 1 को मृतक को भाले से केवल एक जानलेवा चोट पहुँचाने की भूमिका सौंपी गई है। यह स्पष्ट नहीं है कि उसने भाले से छाती पर छिद्रित घाव किया था या कंधे पर, क्योंकि मृतक-अपीलकर्ता, मेहरबान को भी वैसी ही भूमिका सौंपी गई है।

41. सर्वोच्च न्यायालय ने **रफ़ीक़ (पूर्वोक्त)** के वाद में, अपीलकर्ता की सज़ा और दोषसिद्धि को बदल दिया है। अपीलकर्ता ने मृतक के दिल में चाकू से एक ही चोट पहुँचाई थी। न्यायालय ने दोषसिद्धि के आदेश में बदलाव करते हुए आजीवन कारावास को भा.दं.सं. की धारा 304 के पहले भाग के तहत सज़ा में बदल दिया, और अभियुक्त-अपीलकर्ता को पाँच साल के कठोर कारावास और 2500 रुपये के जुर्माने की सज़ा सुनाई।

42. इसलिए, हम अपीलकर्ताओं की दोषसिद्धि को भा.दं.सं. की धारा 302/149 से बदलकर 304/149 कर देते हैं, और अपीलकर्ताओं की सज़ा को आजीवन कारावास से घटाकर पाँच साल के कारावास और 25,000 रुपये के जुर्माने में बदल देते हैं। अपीलकर्ता संख्या 7 और 11 पर दूसरे पक्ष को लाठियों से चोट पहुँचाने का आरोप था; इसलिए, आत्मरक्षा के उनके अधिकार का प्रयोग उन पर किए गए हमले के अनुपात में ही था। अतः, अपीलकर्ता संख्या 7 और 11, यानी मुंशी जी और कृष्ण पाल की दोषसिद्धि को रद्द किया जाता है।

43. अपीलकर्ता संख्या 1, यानी बट्टू सिंह, ज़मानत पर है; उसके ज़मानत बंधपत्र रद्द किया जाता है और ज़मानतदारों को उन्मोचित किया जाता है। उसे तत्काल आत्मसमर्पण करने और अपनी शेष सज़ा पूरी करने का निर्देश दिया जाता है। उसके द्वारा पहले ही काटी जा चुकी सज़ा की अवधि को इसमें समायोजित किया जाएगा।

44. अपीलकर्ता संख्या 7 और 11, यानी मुंशी और कृष्ण पाल, को सभी आरोपों से बरी किया जाता है; उनके जमानत बंधपत्र रद्द किया जाता है और ज़मानतदारों को उन्मोचित किया जाता है। उन्हें आत्मसमर्पण करने की आवश्यकता नहीं है।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



45. ऊपर उल्लिखित आपराधिक अपील को **आंशिक रूप से स्वीकार** किया जाता है।

46. कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि वह विचारण न्यायालय का अभिलेख वापस भेजे और दो सप्ताह के भीतर इस निर्णय की सूचना विचारण न्यायालय को दिया जाये।

(न्यायमूर्ति जय कृष्ण उपाध्याय) (न्यायमूर्ति सिद्धार्थ)

17 फरवरी, 2026

रुचि अग्रहरि

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”